Regarding strengthening the School education infrastrcture in Bihar in view of land, lectricity connection and various other basic requirements

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : सभापति महोदया, मैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक गंभीर मुद्दे को इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । औरंगाबाद लोक सभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 110 प्राथमिक विद्यालय वर्षों से भूमिहीन हैं । जबकि अनेकों ऐसे विद्यालय हैं, जिन्हें किराये के मकान, सामुदायिक भवन और अन्य विद्यालयों में टैग किया गया है, वहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है । जिस विद्यालय में जमीन उपलब्ध है, वहां निर्माण कार्य रुका हुआ है या निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ है ।

महोदया, पूरे राज्य के विद्यालयों की स्थिति और भी चिंताजनक है । 15,000 से अधिक विद्यालयों में बेंच और डेस्क उपलब्ध नहीं है । 20,000 विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन नहीं है । केवल 25 प्रतिशत विद्यालयों में ही कंप्यूटर की व्यवस्था है । एएसईआर 2024-25 की रिपोर्ट कहती है कि कक्षा एक के 31 प्रतिशत बच्चे आज भी अंकों की पहचान नहीं कर पाते हैं और कक्षा पांच के 40 प्रतिशत बच्चे साधारण जोड़-घटाव भी नहीं कर पाते हैं ।

महोदया, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने और भूमिहीन विद्यालयों के लिए विशेष पैकेज दिया जाए, ताकि वहां विद्यालयों का निर्माण हो सके । केन्द्र सरकार यह महत्ती कृपा करे ।